

- * किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी आर्डिनैस का अनुमोदन होना आवश्यक है — राज्य की विधायिका द्वारा
- * राज्यपाल की नियुक्ति करता है — भारत का राष्ट्रपति
- * किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद — 155 के तहत होती है
- * राज्यपालों के संदर्भ में कथन सत्य है
 - (i) वह राज्य की विधायिका का अंग होता है।
 - (ii) वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है।
 - (iii) उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं।
- * कथन (A): "राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"
 - कारण (R): "राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है।"
 - (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- * राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं
 - कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से
- * राज्यपाल उत्तरदायी होता है — राष्ट्रपति के प्रति
- * भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है — राज्यपाल
- * भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है
 - राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध
- * स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनीं—
 - सरोजिनी नायडू (उ.प्र.)
- * पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थीं — पद्मजा नायडू
- * प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है,
 - सरोजिनी नायडू की स्मृति में
- * राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था
 - रघुकुंतिलोक शर्मा
- * भारत में राज्य विधानपालिकाओं (State Legislatures) का उच्च सदन है — विधानपालिका परिषद
- * विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है — 4 माह तक
- * राज्य में धन विधेयक (मनी बिल) प्रस्तुत किया जा सकता है — केवल विधानसभा में
- * राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर — राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
- * राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है — अनुच्छेद 171 के अंतर्गत
- * राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है
 - संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा
- * किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, भारतीय संविधान के— — अनुच्छेद 169 में
- * भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है — राज्य विधानसभा के उत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा
- * उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है — कुल सदस्यों का 1/6
- * इनको बंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है — राज्य विधान परिषदों को
- * यहां अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 में उसके लिए उपबंध है — मध्य प्रदेश
- * राज्य विधान परिषद के विषय में सही है—
 - (i) यह एक स्थायी सदन है।
 - (ii) वह भंग नहीं किया जा सकता।
 - (iii) प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
 - (iv) इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
- * भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है — अनुच्छेद 170
- * अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में साठ से कम सदस्य नहीं होंगे — सिक्किम
- * भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं — 500
- * राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है — भारत का निर्वाचन आयोग
- * विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है — उत्तर प्रदेश में

राज्य विधानमंडल

- * मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है—
 - (i) वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है।
 - (ii) वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
 - (iii) उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है।
- * भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है—
 - राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है

- * राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है — राज्यपाल
- * विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है — 25 वर्ष
- * यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) पद त्यागना चाहे, तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए — उपाध्यक्ष को
- * विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर बना रहता है — विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक।
- * बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है — छः माह तक
- * राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है — राज्य विधानसभा द्वारा
- * राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है — राज्यपाल द्वारा
- * सही कथन है — कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम हो।
- * भारत में एकमात्र राज्य है, जहां "सामान्य (कॉमन) सिविल कोड" लागू है — गोवा
- * वर्ष 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थीं — 5
- * किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है — (i) मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। (ii) सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। (iii) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं।
- * मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं— (i) मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। (ii) मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। (iii) मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद् के समक्ष रखता है।
- * मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है — अनुच्छेद 167
- * जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य-अवधि होती है — छह वर्ष
- * भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थीं — उत्तर प्रदेश में
- * भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी — सुचेता कृपलानी

- * जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में 'सदर-ए-रियासत' से 'राज्यपाल' में बदल दिया गया — जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठें संशोधन द्वारा
- * राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है

I. भारत के राष्ट्रपति के

II. राज्यसभा के सदस्यों के

III. राज्य विधान परिषद के सदस्यों के

- * 'राज्य की आकस्मिक निधि' की स्थापना के लिए उत्तरदायी है — किसी राज्य का विधानमंडल
- * सही कथन है — किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय

- * उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं — राज्य की समेकित निधि से
- * उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है — 62
- * सही कथन है— (i) पंजाब, हरियाणा और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है।
- * भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है— — चौबीस
- * जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, तो वह अधीन होता है— — उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के
- * उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं — संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार
- * यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है — इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- * अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है — कलकत्ता
- * एक से अधिक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए है — बंबई उच्च न्यायालय
- * मार्च, 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं — मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर

- * उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं (संघ राज्य-क्षेत्र शामिल नहीं हैं)

नोट — संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं—

- (1) गुवाहाटी उच्च न्यायालय - अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मिजोरम। (2) बंबई उच्च न्यायालय - महाराष्ट्र और गोवा। (3) पंजाब एवं हरियाणा - पंजाब और हरियाणा।
- (4) तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना।

- * उच्च न्यायालयों में से सबसे अधिक "बेंच" हैं

नोट — कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और दो बेंच ग्वालियर और इंदौर हैं, मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ बंबई और तीन बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और तीन बेंच कोहिमा, आइजोल, ईटानगर हैं। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थीं, परंतु मार्च, 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात् अब तीन बेंच शेष रह गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3-3 बेंचें हैं।

- * उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं

— मूल अधिकारों का संरक्षण

- * एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह, ऐसा कार्य करे, जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट (याचिका) को कहा जाता है

— हैंडमस

- * जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे कहते हैं—

— परमादेश

- * राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है

— परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार

- * रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है

— प्रतिषेध (प्रोहिबिशन)

- * एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी की जाती है

— एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण (रिव्यू) हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे।

- * एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है

— उत्प्रेषण

- * कथन (A) : न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना, न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण (R) : न्यायिक सक्रियता वाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

— A तथा R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।

- * कथन (A) : जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है।

कारण (R) : जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है।

— (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R),

(A) का सही स्पष्टीकरण है।

- * कथन (A) : भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है।

कारण (R) : भारतीय संविधान "उच्चा वस्तुओं से भरा बैला है"।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए

— (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।

- * कथन (A) : भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है।

कारण (R) : सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है।

— (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

- * बाबरी मस्जिद/राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ न्यायपीठ) के समक्ष है, का प्रकार है -

— स्वतन्त्राधिकार मुकदमा (Title suit)

- * सही कथन है—

— भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है।

- * एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबंधित करता है

— राष्ट्रपति को

- * 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया

— न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ

- * भारत में चलित न्यायालय (Mobile Court) इसका मानसपुत्र है—

— डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

- * प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है

— तीन माह तक

- * 'विधि आयोग' के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन दिया है कि "प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिये"

— न्यायाधीश एच.आर. खन्ना

- * 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के संदर्भ में सही है

— वह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है।

केंद्र-राज्य संबंध

- * भारत में केंद्र-राज्य संबंध प्रभावित होते हैं—
 1. संविधान के प्रावधानों से
 2. नियोजन प्रक्रिया से
 3. राजनीतिक हिंसा के अंतर्विरोध से
 4. हुकूम चलाने की इच्छा प्रबलता से
- * केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है
 - अनुच्छेद 268-281 के अंतर्गत
- * भारत में केंद्र-राज्य संबंध निर्भर करते हैं
 1. संवैधानिक प्रावधानों पर
 2. परंपराओं तथा व्यवहारों पर
 3. न्यायिक व्याख्याओं पर
 4. वातवीत के लिए यंत्रविन्यास पर
- * एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं—
 1. संघ और राज्यों के बीच संबंध
 2. राज्यों के मध्य संबंध
 3. समन्वय के लिए तंत्र
 4. विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र
- * केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है, शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं
 - अनुच्छेद 245 तथा 246
- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है
 - राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से
- * अनुच्छेद-249 के खंड (1) के अंतर्गत पास्ति प्रस्ताव प्रवृत्त नहीं रहेगा
 - एक वर्ष से अधिक समय के लिए
- * वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, उल्लिखित हैं
 - समवर्ती सूची में
- * केंद्र-राज्य संबंध उल्लिखित हैं
 - 7वीं अनुसूची में
- * विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है
 - सातवीं
- * केंद्र-राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं
 - भाग XI में
- * भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं
 - संसद में
- * भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को
 - संघीय सरकार को दिया है
- * केंद्र-राज्य संबंधों को विशेष रूप से 'यूनिसेपल संबंध' कहा गया है
 - वितीय मामलों में राज्य पर केंद्र के निबंधन के प्रसंग में
- * संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है
 - अनुच्छेद 355 में
- * भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधित्तर संस्था/संस्थाएं हैं
 - राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन
- * झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ
 - 8 अगस्त, 1995 को
- * भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है
 - अनुच्छेद 263 के अनुसार
- * अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है
 - संवैधानिक
- * सही सुमेलित है—
 - अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262
 - अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956
 - राष्ट्रीय जल नीति, 1987
- * क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है
 - संसदीय कानून द्वारा
- * कथन (A) : केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। कारण (R) : राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।
 - (A) और (R) दोनों अपनी जगह सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
- * विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है— अनुच्छेद 265 में कहा गया है
- * सरकारिया आयोग गठित हुआ था, समीक्षा करने के लिए
 - संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की
- * सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है
 - केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से
- * अभिकथन (A) : सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण (R) : जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।
 - (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- * स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद, जो 'अंतर-सरकारी परिषद्' के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया
 - सरकारिया आयोग ने
- * भारत में संघ-राज्य संबंध से संबंधित है
 - सरकारिया आयोग, राजमन्मार समिति, पुंछी आयोग
- * संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं
 - नहीं
- * राज्य सरकारों को कृषि आय कर समनुदेशित करता है
 - भारत का संविधान
- * एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है
 - कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर

आपात उपबंध

- * भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? — अनुच्छेद 355 के अंतर्गत
- * भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है — युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह
- * आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है — आंतरिक अशांति
- * भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'राष्ट्रीय आपातकाल' की घोषणा की जा सकती है — अनुच्छेद 352 के अनुसार
- * इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है—
— बाह्य आक्रमण, राज्यों में सैन्यिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट
- * भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं (अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त)
— अनुच्छेद 359 के अंतर्गत
- * भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है
नोट : अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं जबकि अन्य मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर, 44वां संविधान संशोधन) को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहां उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायालयों द्वारा केवल उनके प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है।
- * प्रायः राज्यों में 'राष्ट्रपति शासन' लागू किया जाता है — गवर्नर के तहत पर
- * इस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान है
नोट : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में सैन्यिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति (अनुच्छेद 370) को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (1964 से) के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में सैन्यिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया है।
- * संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित कथन सही हैं—
(i) राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है।
(ii) इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
(iii) इस उद्घोषणा का दो माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए।

- * संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है — 1 माह अंतराल में
- * "राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है" कहा था — कै.एम. नायडियार ने
- * भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है — वित्तीय आपात की उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है — अनुच्छेद 360 का
- * भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है — कभी नहीं
- * भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है — तीन प्रकार के
- * राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि — आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल एक वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है।
- * राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है — 3 वर्ष तक
- * आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है — संसद द्वारा

वित्त आयोग

- * सामान्य रूप में भारत में प्रति पांच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है — केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
- * संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है — वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर
- * भारत में, शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर 1. संघ द्वारा लगाए जाते हैं
2. राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं
- * वित्त आयोग का मुख्य कार्य है — केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
- * वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति मेजने में मुख्य रूप से संबंधित है: — राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से
- * भारत में वित्त आयोग का कार्य है — आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहाय्यार्थ अनुदान निर्धारण

- * कथन (A): राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
कारण (R): संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता— (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
- * संघ एवं राज्यों के बीच कर्षण के विभाजन संबंधी प्रावधानों को
— राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
- * 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे — सी. रंगराजन
- * 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे — विजय केलकर
- * 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष था — वाई.वी. रेड्डी
- * वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा — भारत का राष्ट्रपति
- * वित्त आयोग का गठन किया जाता है, प्रत्येक — पांचवें वर्ष
- * राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है
— यह एक संवैधानिक संस्था है
- * संविधान लागू होने के पश्चात अब तक वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं—

नोट : अब तक 14 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। 14 वें वित्त आयोग का गठन जनवरी, 2013 में वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2014 को सौंपी।

- * वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है, और — चार अन्य सदस्य

योजना आयोग

- * योजना आयोग का अंत किया — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
- * योजना आयोग की स्थापना हुई थी — 15 मार्च, 1950
- * योजना आयोग की स्थापना की गई
— संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर
- * संविधानोत्तर संस्था है — नीति आयोग
- * वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर बिलय का प्रस्ताव दिया था
— एम.वी. माथुर ने
- * संवैधानिक निकाय नहीं है — योजना आयोग
- * इन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है

1. राष्ट्रीय विकास परिषद

2. योजना आयोग

3. क्षेत्रीय परिषदें

- * भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे
— पंडित जवाहरलाल नेहरू
- * योजना आयोग के 'पदेन' अध्यक्ष हैं — प्रधानमंत्री
- * नीति आयोग के विषय में सही है
— (i) इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है।
(ii) इसका गठन जनवरी, 2015 में किया गया था।
(iii) यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है।

- * योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्त्व का दर्जा दिया गया है
— भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान
- * कथन (A) : "योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परामर्शित किया गया है", केवल संघ हेतु नहीं, अपितु राज्यों हेतु भी।
कारण (R) : यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है।
— (A) एवं (R) दोनों सही हैं, परंतु (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है (A) का।
- * राष्ट्रीय विकास परिषद—
1. राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है।
2. राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है।
3. राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशानिर्देश प्रदान करती है।
- * राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं
— प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रिगण, राज्यों के मुख्यमंत्री
- * राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है
— पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से
- * राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है
— भारत का प्रधानमंत्री
- * भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित की गई थी
— 6 अगस्त, 1952 को

लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग

- * भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था
— प्रशासनिक सुधार आयोग ने
- * राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी
— भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)
- * ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है — लोकपाल
- * संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था — 1968 में
- * उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है
— द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में
- * सर्वप्रथम लोकयुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी — महाराष्ट्र में
- * * उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है
— राज्यपाल को
- * 2011 में लोकयुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है
— उत्तराखंड
- * वोहरा समिति.....के अध्ययन के लिए बनाई गई थी।
— राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ

- * वह समिति, जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी — **वोहरा समिति**
- * भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी — **राजमन्नार आयोग ने**
- * 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था — **अनुच्छेद 123**
- * मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उद्देश्य था — **मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन**
- * राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में सदस्य होते हैं — **लोक सभा का अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष का नेता तथा राज्य सभा में विपक्ष का नेता**
- * भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में सही कथन है—
— इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं, आयोग के एक सदस्य के रूप एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है।
- * मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में 'लोक सेवक' की परिभाषा दी गई है — **धारा 2(M) के अंतर्गत**
- * कथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो।
कारण (R): उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयुपर्यंत पर (जो भी पहले हो) धारित करता है।
— **(A) तथा (R) दोनों सही हैं।**
- * राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है — **राज्यपाल द्वारा**
- * राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है — **मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना।**
- * संवैधानिक संस्था नहीं है — **मानवाधिकार आयोग**
- * संवैधानिक प्राधिकरण है—
1. राज्य निर्वाचन आयोग, 2. राज्य वित्त आयोग, 3. जिला पंचायत
- * संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित कथन सही हैं— — **इसकी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्रकृति की होगी, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम. एन. वैकटचेतैया कर रहे हैं**
- * संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी, 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं — **एम.एन. वैकटचेतैया**
- * केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल होता है — **5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक**
- * स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया, वह था — **मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता**
- * मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, को गठित करने वाले थे — **मोरारजी देसाई**

- * मंडल आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई — **1980 में**
- * वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है — **धार्मिक कारण**
- * राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है — **राज्यपाल द्वारा**
- * दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है — **भारत के राष्ट्रपति के द्वारा**
- * राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है — **सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर**
- * किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है — **भारत के राष्ट्रपति अनुमोदन से**
- * लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है — **अनुच्छेद 317 के अंतर्गत**
- * भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही है — **इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना-देना नहीं है**
- * संघ लोक सेवा आयोग एक — **संवैधानिक संगठन है**
- * संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है — **राष्ट्रपति को**
- * यूनिफ़ॉर्म पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है — **रोज वैथ्यू**
- * उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यवहार में होते हैं — **राज्य की संचित निधि पर**
- * भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई, वह था — **गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919**

अस्थायी विशेष प्रावधान

- * भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है — **अनुच्छेद 371 में**
- * भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। वह राज्य है— — **जम्मू-कश्मीर**
- * भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-ख में विशेष उपबंध प्रावधानित हैं — **असम के लिए**
- * संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है — **महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए**
- * भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है — **कश्मीर का अलग संविधान है**
- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है — **एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध**

- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है
— जम्मू-कश्मीर राज्य से
 - * भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू-कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं, वे हैं -
— अनुच्छेद 1 एवं 370
 - * जम्मू एवं कश्मीर का 'सदर-ए-रियासत' पदनाम बदल कर 'राज्यपाल' कर दिया गया
- नोट : जम्मू एवं कश्मीर संविधान में छठें संविधान संशोधन अधिनियम, 1965 द्वारा सदर-ए-रियासत नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर-ए-आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया।

चुनाव आयोग

- * मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन हैं—
— (i) मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है, जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है।
— (ii) मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।
- * भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है
— सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष
- * भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है
— 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- * मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है
— संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर
- * निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है
— मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है
— राष्ट्रपति द्वारा
- * भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है
— अनुच्छेद 324 के अंतर्गत
- * भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं—
I. संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना।
II. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना।
III. निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं निबंधन।
- * राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है
— भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा
- * भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं
1. वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली।
2. एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुषांगिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली।
- * भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है
— निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना
- * संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेंगे। — भारत के निर्वाचन आयोग की
- * यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि (जमानत राशि) खो देता है, तो उसका अर्थ है कि
— निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी
- * न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है — संसद द्वारा
- * भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है
— विधिक अधिकार (एक अधिनियम के अंतर्गत)
- * नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया, इस आम चुनाव में — 1989 के
- * केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई
— 61 वें संशोधन (1989) द्वारा
- * 'निर्गम मत सर्वेक्षण' के विषय में कथन सही है
— निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया।
- * जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में सही हैं
— (i) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि के होने पर दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी।
(ii) लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अम्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है।
(iii) चुनाव लड़ने वाले किसी अम्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता।
- * दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी
— लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधीकरण की

* दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था

— निर्वाचन सुधारों से

* उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, जहां

— द्वि-दलीय प्रणाली विकसित हुई है

* कथन (A) : संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात् निर्वाचन आयोग को दी गई हैं।

कारण (R) : निर्वाचन आयोगों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है।

— A और R दोनों सही हैं, किंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं है A का

* निर्वाचन आयोग को 'तीन सदस्यीय आयोग' बनाया गया

— 1989 से

* इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता

— स्थानीय निकायों का

* परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है—

1. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

* राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है — 25 जनवरी को

* कथन (A) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है।

कारण (R) : आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग, हिताँ और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के व्योचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है।

— (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R) सही व्याख्या है (A) की

* आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रियाप्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है — अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को

* कथन (A) : राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है।

कारण (R) : ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। — (A) सही है, किंतु (R) गलत है।

राजनीतिक दल

* भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है, यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम—

— चार राज्यों में

* किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि

— वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा

चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है।

* किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है, जब वह—

(i) उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं चार या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनावों या उन राज्यों के विधानसभा

चुनावों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत

और साथ ही कम से कम चार लोकसभा सीटें प्राप्त हों।

(ii) उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम

2 प्रतिशत सीटें प्राप्त हों तथा ये सदस्य कम से कम

3 राज्यों से चुने गए हों।

(iii) वह दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य

स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो।

* 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' में 'राष्ट्रीय' शब्द प्रभावित था

— ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से

* 1999 में विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ

— कांग्रेस पार्टी के

* राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है :

1. यह बयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

2. प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी।

3. धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा।

4. राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी।

* भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष थे

— ए.बी. वाजपेयी

* 'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी' का संस्थापक थे — बी.आर. अम्बेडकर

* डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्थापना की थी — ऑल इंडिया सिक्कूल्ड

कास्ट्स फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी

* सही सुमेलन इस प्रकार है—

(राजनैतिक दल)	(गठन वर्ष)
सी.पी.आई.	1920
सी.पी.एम.	1964
ए.आई.ए.डी.एम.के.	1972
तेलगूदेशम	1982

* भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सी.पी.आई. और सी.पी.आई.एम. में हुआ था

— 1964 में

* कथन (A) : भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ बायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं।

कारण (R) : वह बहुत से बीजों की वृद्ध विस्तार में चर्चा करता है।

— दोनों A और R सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

- * कथन (A) : भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले।

कारण (R) : बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है।

— A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

- * कथन (A) : संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए तैत्तिशत प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

कारण (R) : चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दल, बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके तैत्तिशत प्रतिशत को, महिलाओं के लिए निबत कर सकते हैं।

— A गलत है, परंतु R सही है।

- * भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है — चुनाव आयोग को

- * भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं—

1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है।

3. राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है, जिसे चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है।

- * कथन (A) : भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है।

कारण (R) : अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं।

— A तथा R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।

- * आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है

— दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय-समय पर होता है।

- * दल-बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, वह थी

— 15 फरवरी, 1985

- * राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष

— 1985 में

- * दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था

— जम्मू एवं कश्मीर राज्य में

- * लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए

नोट : लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या 545 का न्यूनतम 10% अर्थात् 54.5 या 55 सदस्य संबंधित पार्टी या गठबंधन का होना चाहिए।

- * साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से 'भू-पोर्टम' आंदोलन चलाया था

— आंध्र प्रदेश में

- * 'कामराज योजना' का उद्देश्य था

— भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना

- * कथन (A) : भारत में लिखित संविधान है।

कारण (R) : शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आवंक्षाओं का संकेतक है।

— (A) और (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

संविधान संशोधन

- * कथन सही है

— मिनर्वा मिल्स वाद, 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39(ख) एवं (ग) में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है।

- * संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति "सहमति देनी होगी" शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है

— चौबलिसवां संशोधन

- * भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है

— संविधान संशोधन विधेयक

- * भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है

— अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत

- * भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है

— या तो लोकसभा में या राज्यसभा में

- * भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समुष्टि आवश्यक है—

1. संविधान के संघीय प्रावधान

2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार

3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया

- * वे विषय, जिन पर कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांविधानिक संशोधन संभव है — (1) राष्ट्रपति का निर्वाचन

(2) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

(3) सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची

- * भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन (Amendment Act) विधेयक लाया गया

— 1951

- * उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब

— विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।

- * संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, संबंधित था — कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि-भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से
- * भारतीय संविधान में 9 वीं अनुसूची परिवर्धित हुई

— प्रथम संशोधन द्वारा

- * संविधान का 93 वां संशोधन (विधेयक) संबंधित है — 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से

- * 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा व अधिकार' लागू किया गया — वर्ष 2010 से

- * अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है — 93वें संशोधन के अंतर्गत

- * सही सुमेलन इस प्रकार है
(i) 69वां संविधान संशोधन : दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा;
(ii) 75वां संविधान संशोधन : राज्य स्तरीय किराय अधिकरणों की स्थापना (iii) 80वां संविधान संशोधन : दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकारना (iv) 83वां संविधान संशोधन : उरुपाबल प्रदेश में पंचायतों में अनु. जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहां का समाज आदिवासी समाज है।

- * अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा गया — 97वां संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा

- * दिल्ली 'नेशनल कैपिटल क्षेत्र' बना — 69वां संशोधन द्वारा

- * पहली बार संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधान किया गया — 52वां संशोधन द्वारा

- * भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधनों में से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया

— 58वां संशोधन, 1987 के द्वारा

- * मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है — 61वां संशोधन

- * भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है — लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से

- * भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि — संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता।

- * भारत में, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है — संसद

- * सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया — गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में

- * लघु संविधान कहा गया था — 42वां संविधान अधिनियम को
- * यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39(b) और (c) में वर्णित हैं, प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है — 25वां संशोधन

- * संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है — 42वां

- * केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार, क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा — 91वां संविधान संशोधन

- * सिक्किम एक नया राज्य बना — 36वें संशोधन द्वारा

- * मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया — 53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा

- * 'शिक्षा का अधिकार' प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21-A संविधान में जोड़ा गया है — 86वां संशोधन द्वारा

- * 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार से है — सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन

- * सही सुमेलन इस प्रकार है—

- | | |
|--------------------|--|
| (i) 13वां संशोधन | — नगालैंड |
| (ii) 18वां संशोधन | — राज्य को पुनर्निर्भाषित किया गया |
| (iii) 39वां संशोधन | — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्वीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती |
| (iv) 52वां संशोधन | — दल-बदल अधिनियम |

राजभाषा

- * यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा — अनुच्छेद 350-क में

- * सही कथन है—
— बोडो संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है।

- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम 'राजकीय भाषा आयोग' का गठन हुआ था

— 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में

- * भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा चार भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई

— संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम

- * संविधान की आठवीं सूची में नहीं है — भोजपुरी

- * 71वें संशोधन से संविधान की आठवीं अनुसूची में तीन भाषाएं जोड़ी गई थीं — **नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी**
- * भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है — **22**
- * संविधान में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है — **अनुच्छेद 345 में**
- * संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है — **उत्तराखंड ने**
- * भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है — **कम से कम 2/3 बहुमत से**
- * संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं से बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं — **हिंदी, इसके बाद बंगाली**
- * भारतीय भाषाओं को, मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों को, सही अवरोही क्रम है — **बंगाली, तेलुगू, मराठी, तमिल**
- * हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग है — **40**
- * विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं — **मंदारिन के**
- * भाषा बलूचिस्तान की है, किंतु भाषाशास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है — **ब्राहुई**

पंचायती राज व सामुदायिक विकास

- * पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है — **राज्य का विधानमंडल**
- * पंचायतों के संबंध में सही कथन है — **भारत के संविधान के भाग IX में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है।**
- * पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है — **राज्य सरकार द्वारा**
- * पंचायती राज सम्मिलित किया गया है — **राज्य सूची में**
- * पंचायत चुनाव होते हैं — **प्रत्येक पांच वर्षों में**
- * पंचायतों से संबंधित है — **राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सभी पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित होगा, एक पंचायत के भंग होने के छः माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा।**
- * पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए 'वित्त आयोग' का गठन करता है — **संबंधित राज्य का राज्यपाल**
- * भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे — **पी.वी. नरसिंहराव**

- * पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया — **1993 में**
- * कथन (A) : पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रिया-कलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है।
कारण (R) : ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। — **(A) सही है, परंतु (R) गलत है।**
- * 'पंचायती राज व्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है — **73वां संविधान संशोधन**
- * भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है — **73वें संशोधन के अंतर्गत**
- * पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका/शक्ति है-
1. ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।
2. ग्राम सभा के पास लघु बनेपज का स्वामित्व होता है।
- * पंचायती राज एक व्यवस्था है —
1. स्थानीय स्तर पर स्वशासन की।
2. जैव-संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की।
3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की।
- * 'ग्राम सभा का अभिप्राय है — **ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग**
- * अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता करता है — **उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए**
- * पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है — **विकास में जन-भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण**
- * राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है — **अनुच्छेद 40**
- * भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्वक कदमों हेतु परामर्श देता है — **ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में**
- * पंचायती राज को.....के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया — **भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन**
- * मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया है — **अनुच्छेद 43**
- * सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं — **इनमें सरकार की तीन श्रेणियां होती हैं, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं**

- * पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है
 - ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण
- * पंचायती राज से संबंधित सही कथन है—
 - (i) पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है।
 - (ii) यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है।
 - (iii) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है।
- * पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है
 - लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना
- * सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है
 - स्थानीय जनता की
- * भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है
 - शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास
- * CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था
 - बलवंत राय मेहता समिति
- * सही सुमेलित है—

सूची-I (समितियाँ)	सूची-II (सुझाव)
A. बलवंतराय मेहता	1. त्रिस्तरीय पद्धति
B. अशोक मेहता	2. द्विस्तरीय पद्धति
C. एल.एम. सिंघवी	3. स्थानीय स्वशासन पद्धति
D. जी.बी.आर. राव	4. प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार
- * बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई
 - राजस्थान में
- * भारत के 'पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार (शिल्पी)' कहा जाता है
 - बी.आर. मेहता
- * भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और.....में प्रारंभ की गई थी।
 - आंध्र प्रदेश
- * प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को किया गया था
 - नागौर (राजस्थान) में
- * बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार :
 - जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था
- * पंचायती राज से संबंधित समितियाँ कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हैं—
 - बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.बी. के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति
- * अशोक मेहता समिति ने 'पंचायती राज' के लिए संस्तुति की थी
 - द्विस्तरीय प्रतिमान की
- * पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी
 - एल.एम.सिंघवी कमेटी द्वारा
- * संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं
 - ग्यारहवीं सूची में
- * संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है—
 1. पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए
 2. महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए
 3. राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं
 4. 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण।
- * भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए हैं
 - 29
- * राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है
 1. राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है।
 2. राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है।
- * पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है—
 - I. नगर पंचायत, II. ग्राम पंचायत, III. क्षेत्र पंचायत
- * 73वें संविधान संशोधन का अभिप्राय करने वाला पहला राज्य है—
 - मध्य प्रदेश
- * 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 निर्दिष्ट करता है -
 - देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना
- * महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान (Indian Constitution) में संशोधन करके दिया गया है, वह है -
 - 1992 का 73 वां संशोधन
- * संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है
 - अनुच्छेद 243 घ
- * 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा
 - स्वशासन व्यवस्था
- * पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है
 - ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना
- * 'तृण मूल लोकतंत्र' से संबंधित है
 - पंचायती राज पद्धति

- * पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी
 - लोकतंत्र की शक्तियों के विवेकीकरण के लिए
- * पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं—
 - ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद
- * तीन सौपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है
 - भाग 9 (ix) में
- * एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है
 - राज्य सरकार द्वारा
- * एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, यदि उसने पूर्ण कर ली है
 - 21 वर्ष की आयु
- * सही कथन है
 - पंचायत के समय पूर्व बंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है।
- * वह कालेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद (Municipal Council) में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि
 - उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो।
- * भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है
 - न्यायिक पुनर्वीक्षण (Judicial Review)
- * पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है
 - बिहार में
- * स्थानीय शासन की विशेषता है—
 - (a) वैधानिक स्थिति
 - (b) स्थानीय समुदाय की भागीदारी
 - (d) कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति
- * राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है—
 - अनुच्छेद 243 (आई) के अनुसार
- * किसी राज्य के राज्यपाल को, उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है
 - राज्य वित्त आयोग
- * शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया
 - 74वां संशोधन द्वारा
- * मेयर का कार्यकाल होता है
 - 5 वर्ष का
- * भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ZJ) के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है
 - 21
- * राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों (Local Bodies) पर नियंत्रण नहीं होता
 - नागरिकों की शिकायतों में
- * नगरपालिकाओं से संबंधित है
 - भाग IX A
- * सही सुमेलन है

उप-प्रभाग स्तर पर जिला परिषद	- असम
बंडल प्रजा परिषद	- आंध्र प्रदेश
जनजातीय परिषद	- मेघालय
ग्राम पंचायतों का अभाव	- मिजोरम
- * जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं
 - 20 और 5
- * कथन (A): स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है।
 - कारण (R) : संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है।
 - दोनों A और R सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है
- * कथन (A) : स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है।
 - कारण (R) : संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद, स्थानीय शासन संविधान के सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है।
 - (A) गलत है, परंतु (R) सही है।
- * यदि पंचायत बंग होती है, तो निर्वाचन होंगे
 - 6 माह के अंदर
- * भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में, कथन सही है
 - (a) राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे, तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है।
 - (b) जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए।
 - (d) उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बैठे हुए बात या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है।
- * पंचायती राज संस्था नहीं है
 - नगालैंड में
- * नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है
 - ये सभी स्थान :
 - जो नगरपालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हो
- * किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है
 - संबंधित राज्य का राज्यपाल

- * भारत में महानगर योजना समिति
 1. भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है।
 2. उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारम्भ तैयार करती है।
- * भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है
 - अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से
- * पंचायत की संरचना के संबंध में सही है—
 1. किसी राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा।
 2. ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
 3. ऐसे राज्य जिन्होंने जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे।
- * पंचायत समिति के सदस्य
 - जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं
- * पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा
 - राज्य के राज्यपाल द्वारा
- * पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है
 - खंड स्तर पर
- * उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है
 - जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही
- * उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है
 - (i) अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा।
 - (ii) अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से।
- * 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है
 - किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य
- * महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, सम्पादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी है
 - ग्राम पंचायत की
- * सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है
 - राष्ट्रीय प्रसार सेवा

कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध

- * कथन (A) : 'अल्पसंख्यक' शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है।
कारण (R) : अल्पसंख्यक आयोग संविधानिक निकाय नहीं है।
— A और R दोनों सही हैं, परंतु A की सही व्याख्या R नहीं करता है।
- * सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं — मध्य प्रदेश में
- * अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान किया गया है
— 338 और 338A के अंतर्गत

- * अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कथन सही हैं—
 - (a) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियाँ प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा सन् 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं।
 - (b) इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है।
 - (d) कोई जनजाति, राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है।
- * अनुसूचित जनजाति का दर्जा : — वर्मनिष्ठा से तटस्थ है
- * भारत के संविधान में लोक सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है — अनुच्छेद 330 में
- * भारतीय संविधान का भाग-16 (अनुच्छेद 330 से 342 तक) संबंधित है — लोक सभा में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से
- * लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है — अनुच्छेद 331 के अंतर्गत
- * किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु, शक्ति संपन्न सांविधानिक प्राधिकारी है
— भारत का राष्ट्रपति

प्रश्न विविधा

- * संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था — 1945 में
- * संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है — 24 अक्टूबर
- * संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है — 5
- * संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कथन सही है—
 - (a) सभी प्रक्रियेतर मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक हैं और उन नौ में परिषद के स्थायी सदस्यों के सहमति मत होने भी आवश्यक हैं।
 - (b) सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है।
 - (c) निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प पर रोक लगा सके।
- * प्रथम अफ्रीकी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं
— बुतरोस बुतरोस घाली
- * संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा
— वू. शांट का